मुख्यधारा से अब भी कटे हैं बिरहोर

क्र सं0	प्रखंड का नाम	परिवार की संख्या	आबादी	खेती योग्य भूमी	बंजर भूमि	अशिक्षा का दर	साक्षर दर
1	कोडरमा	198	766	10 स्क्य	61 स्कयार	635	131
2	धनबाद	44	137	123	00	126	12
3	बेकारो	47	297	00	50	280	17
4	गिरिडीह	77	258	00	33	221	37
5	चतरा	415	1256	00	00	00	00
6	हजारीबाग	580	1873	00	00	1602	271
7	सराईकेला	24	76	00	00	76	00
8	प. सिंहभुम	192	585	00	00	637	48
9	सिमडेगा	35	174	05	05	140	34
10	गुमला		141	00	00	00	00
11	लोहरदगा	10	58	00	00	00	00
12	रांची	37	636	00	00	00	00
13	गढ़वा		00	159	00	00	00
14	लातेहार		00	94	00	00	00

- हर गांव में स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापन हो गांव में 15 दिन में एक दिन डॉ. का आना जाना हो
- बिरहोर टोली में आंगनबाड़ि केन्द्र की स्थापना.
- इनके बीच गाय पालन मुर्गी पालन, बकरी पालन, आदि का योजना को लागू करना.
- आय बढ़ाने के लिए वन उत्पादन के एवं लाह की प्रषिक्षण किया जाना.
- बालिकाओं की रक्षा की पर सोचना होगा
- मनरेगा का काम बिरहोर मांग रहे है.
- बिरहोर को वन भूमि पट्टा दे कर उन्हें सिचाई की व्यवस्था कर किसान बनाया जा सकता है.
- भारत सरकार के हस्तकला विभाग के माध्यम से बिरहोर के बन.

आलोका

भारत एक कल्याणकारी देश है यहां सबसे कमजोर वर्ग के लिए अलग से कल्याकारी योजना चलाई जा रही है जिससे लिए करोड़ों का बजट है करोड़ों के बजट और हजारों के आबदी वाला बिरहोर विकसीत नही हो पा रहा है इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं सरकार की इच्छा शक्ति की कमी ने बिरहोर समुदाय के जीवन स्तर को उठाने में सक्ष्म नहीं हो पा रही. वहीं 2005 में वन कानून पारित हुआ जिसके अन्तर्गत वन के अंदर रहने वाले समुदाय को वन पर पट्टा और अधिकार देने की पहल हुई वह भी अधुरा ही रह गया. झारखंड के 24 जिले वाला राज्य में 14 जिले में आदिमजनजाति बिरहोर निवास करते है.

इनका निवास स्थान गांव और शहर से दूर जंगल होता है जहां वे अपने परिवार या अपने समुदाय के छोटे समूह के साथ रहते है. पहले तो वन का घनापन इनके जीविका का आधार था. बदलते परिस्थति ने और जलवायु परिवर्तन ने इन छोटे समुदाय के जीविका पर संकट खड़ा कर दिया. ऐसे स्थिति में आदिमजनजाति के जीवन कोरीडोर के अन्दर पलायन परिवर्तन और श्रम के प्रति इनका आकलन बढ़ा. बिरहोर स्वयं से रोजगार की तलास करने और उत्पादन के साधन के साथ जूड़ते चले गया.

बिहार एककृति राज्य के समय बिरहोर की स्थिति काफी खराब थी झारखंड अलग राज्य बनने के बाद इन समुदाय के लिए राज्य सरकार के आदिमजनजाति कल्याण विभाग ने थोड़ा बहुत काम करने का प्रयास किया जिसमें झारखंड आदिवासी कल्याण सोध संस्थान ने 2002-2003 में सोध झारखंड में रह रहे आदिमजनजाति के स्थिति और जरूरत के साथ उनकी आबादी को निकाला यही नहीं विभाग ने कई इलाकों में जैसे धनबाद और चतरा के कोरी गांव में बिरहोर को खेती के साथ जोड़ इंदिरा आवास कृषि योग्य भूमि, सब्जी की खेती, वृद्व पेशन सोलर सिस्टम के साथ अनपूर्ण योजना के साथ जोड़ा गया. जिससे बिरहोर की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आए वे स्थाई रूप से वही गांव में रह गये जहां वह घुमते हुए पहुंचे थे. उनका अपना देशज ज्ञान के आधार पर रस्सी बनाने, जाल बनाने की कला उन्हे है.इन कला को वों बेच कर अपने परिवार को चलाने में सहयोग करते है. टोटल बिरहोर की संख्या झारखंड में 6579 स्रोत झारखंड आदिवासी कल्याण विभाग रांची झारखंड के 14 जिले जहां आदिमजनजाति बिरहोर समुदाय का रह रहे वहां जंगल की स्थिति अब दैनिय हो गया है.

वहां बिरहोर समुदाय के पास स्वास्थ्य जैसी समस्या लगातार बरकरार बनी हुई है. जहां सरकार के स्वास्थ्य उपकेन्द्र का सही तरीके से काम नहीं कर पाता वही नया तरह के बीमारी के लिए दवा और इलाज पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे है. वहीं बेरोगारी उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है. आजादी के लंबे समय के बाद भी ये समुदा को बेरोजगारी का दंस झेल रहा. आज भारत में सबसे कमजोर कोई समाज है वह आदिमजनजाति समुदाय का समाज है जिनके पास अपने जीवन जीने के लिए कुछ भी नहीं, वह पूरी तरह प्राकृति और अपने श्रम के बल पर जिन्दा है. जिन प्रखंडों में बिरहोर समुदाय के लिए सरकारी सहायता प्रदान कर कृषि के काम से जोड़ा है जिसमें चतरा के कोरी, ईटखोरी बगोदर सिंहभूम हजारीबाग, रांची के इलाका में आत्म निर्भर बन रहे है.

उनका पलायन नहीं हो रहा है, वे अब किसान बन कर उत्पादन के साथ जीवन यापन कर रहे हैं. वही चतरा के चाड़म, गोपालपूर, लातेहार के सरजू इलाके में आज तक इंदिरा आवास योजना लागू नहीं हो पाई है. वहीं इन जिलों में बिरहोर समुदाय पूरे साल भर में 1000 रुपये कमा पाते. धनबाद के तोपचांची प्रखंड में स्वास्थ्य और कुपोशण की स्थिति बरकरार है. वहां बिरहोर समुदाय के बीच शिक्षा का महत्व है यदि इन युवाओं को स्वास्थ्य संबध कार्य में लगाया जाए तो इससे बिरहोर के बीच स्वास्थ्य और कुपोशण की समस्या नहीं रहेगी. पूरे झारखंड में बिरहोर समुदाय भूमिहीन है इन्हें स्थाई रूप से भूमि के साथ जोड़ना चाहिए.

बिरहोर ने समाधान के कई रास्ते बताये और उन्हे आशा है कि सरकार इसे पूरा करेगी. रस्सी को बाजार में पहुंचाया जाए. ऐसी अनुसंशा 2002-2003 में सरकार के पास किया गया है जिसमें कई बिरहोर के जरूरत को घ्यान में रख कर तैयार किया गया. जिससे आज तक पूरा नहीं कर पाए.

सीएसडीएस फेलोशिप के तहत